# Hkkjrh; turk ikVhZ

*(केंद्रीय कार्यालय)*

11 अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

**दूरभाष** : 233005700; **फैक्स** : 23005787


दिनांक : 12 मार्च, 2010

## राज्यसभा में आम बजट पर बहस प्रारंभ करते हुए नेता, प्रतिपक्ष श्री अरूण जेटली द्वारा दिए गए भाषण के संक्षिप्त बिंदु

**(भाषण अपूर्ण है और सोमवार 15 मार्च, 2010 को जारी रहेगा)**

यह बजट विश्व के मंदी से उबरने की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें ठोस विचार दिए जाने की आवश्यकता थी। खेद है कि बजट में ऐसे विचारों का अभाव है। देश के सामने भारी कृषि संकट है, जो घटते उत्पादन, कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अभाव और लगभग उत्पादकता रूद्धता – दोनों मुहानों पर दिखाई दे रहा है। देश में अभूतपर्वू मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्य के बारे में मुद्रास्फीति का बोलबाला है। बजट से आशा थी कि वह नीतिपरक कथन होगा न कि एक विवरणात्मक बयान, जिससे इन चुनौतियों को सुधारा जाता।

### मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति पहले ही बढ़कर 8.56 प्रतिशत हो गई है। विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 14 से लेकर 17 प्रतिशत तक है। खाद्य मूल्य मुद्रा स्फीति 19 प्रतिशत है। आर्थिक सर्वेक्षण (पृष्ठ 65) में स्पष्ट उल्लेख है कि आज आलू, सब्जियां, चावल और गेहूं जो आवश्यक सभी वस्तुएं हैं, अभाव की शिकार हैं। संप्रग शासित राज्यों में जमाखोरी के खिलाफ कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए बफर स्टॉक से यथेष्ट मात्रा में खाद्य पदार्थ जारी नहीं किए, न ही बाजार की कमी को दूर करने के लिए समय पर आयात किए गए। सर्वेक्षण (पृष्ठ 201) में स्पष्ट उल्लेख है कि 1 जनवरी, 2010 को खाद्यन्नों की स्टॉक स्थिति 47.4 मिलियन टन थी। यह बफर स्टॉक के मानक के लगभग दोगुनी थी, तो भी सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप करने में सुस्ती बरती। बजट ने मुद्रास्फीति को सुधारने के लिए क्या किया। इसके द्वारा उत्पादन शुल्क 2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। बजट में सीमेंट और वाहनों के जो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक होते हैं, के दामों में और अधिक वृद्धि कर दी। बजट के द्वारा कच्चे तेल, पैट्रोल और डीज़ल पर अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। इसका शुद्ध प्रभाव यह हुआ कि इसके कारण समस्त कृषीय खाद्य, रीयल एस्टेट और वस्तुतः सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। सेवा करों में वृद्धि लोगों के साथ क्रूर मजाक है।

## सेवा कर

स्वास्थ्य रक्षा भी सेवा कर के अंतर्गत आती है। प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल और अधिक महंगी क्यों होनी चाहिए ? वैतनिक कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य की जांच कराए जाने पर 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। अमीर आदमी सेवा कर के बिना अस्पताल का बिल अदा कर सकते हैं तथा बीमा पर निर्भर करने वाले सभी लोगों के बिलों में सेवा कर की राशि भी जुड़ जाएगी। यह उनके द्वारा दिए गए बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के अतिरिक्त खर्च होगा। वायुयान यात्री परिवहन – विशेषतया कम लागत वाले एयर लाइन आजकल लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वे मध्यम वर्ग के लिए भी जरूरी हो गए हैं। तथा उनका पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सेवा कर ने उनको 10 प्रतिशत और अधिक महंगा बना दिया है। अब सभी आई.टी. और आई.टी. संबंधी सेवाएं सेवा कर की जद में हैं। शैक्षित प्रशिक्षण संस्थानों पर सेवा कर से शिक्षा और महंगी हो जाएगी, जो एकमुश्त अपार्टमेंट खरीद रहे हैं उनको सेवा कर से छूट है। किंतु, उस मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग जो किश्तों पर निर्भर करता है, उसको डेवलपर को सेवा कर जोड़कर भुगतान करना होगा।

आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह के प्रोपर्टी रेंटलों पर अब पिछले 1 जून, 2007 से सेवा कर उगाहा जाएगा। किंतु, बड़ा झटका रेलवे द्वारा माल की ढुलाई पर 10 प्रतिशत सेवा कर लगाए जाने से लगा है। अब रेलवे द्वारा सारी माल ढुलाई – कुछ खाद्यान्नों को छोड़कर सेवाकर की जद में आ गई है। बजट जब यह कहता है कि सेवा कर का भार केवल 3,000 करोड़ रूपए है, तब यह सही–सही आंकड़ें नहीं बताता है। वस्तुतः रेलवे द्वारा माल ढुलाई, जिस पर टैक्स लगा दिया गया है से लगभग 6,000 करोड़ रूपए प्राप्त होंगे। सेवा कर का शुद्ध संघात कहीं अधिक है। रेलवे ढुलाई पर 70 प्रतिशत रियायत का वादा किया गया था। दुर्भाग्यवश 27.02.2010 की अधिसूचना संख्या 9/2010 में समूची रेल ढुलाई सेवा कर की जद में है। इसका विशुद्ध प्रभाव यह पड़ा है कि यह एक उच्च कर वाला बजट बनकर रह गया है। यह मुद्रास्फीति करने वाला बजट है पैट्रोल उत्पादों पर कर केवल राजस्व में अंशदान करता है। तेल कम्पनियों को प्रतिपूर्ति की दूसरी किश्त दिए जाने का अब शीघ्र इंतजार है।

## खाद्य अभाव

हमारी जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। 2026 तक इसमें स्थिरता आने की आशा है। वास्तविकता यह है कि हम उस तारीख का भी अतिक्रमण कर सकते है। हमारी खाद्य उत्पादकता नहीं बढ़ रही हैं। कृषि की भूमि घटती जा रही है। क्या बजट को एक आर्थिक नीति निर्धारक वक्तव्य नहीं होना चाहिए था, जिसमें कृषि के घटते क्षेत्र में किस तरह सुधार किया जाए इसका संकेत हो ?

क्या भारत के लिए उच्चतर एफएसआई वाली आवास नीति पर बहस करने का तथा लग्ज़री हाउसिंग, रिज़ॉर्ट और फार्म हाउसों की बजाय अपार्टमेंट में रहने की शुरूआत करने का समय नहीं आ गया

है ? आर्थिक सर्वेक्षण (पृष्ठ 68–69) में दालों, चीनी, चावल, गेहूं, सब्जी और दूध, जो जीने के लिए अतिआवश्यक वस्तु हैं, की खेती में कमी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 207 पर कृषि उत्पादकता की और कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश की निराशाजनक तस्वीर पेश की गई है। क्या बजट में इन मुद्दों को छुआ गया है ? बजट में द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का वायदा किया गया है। पूर्वोत्तर के सात राज्यों में क्रांति केवल 400 करोड़ रूपए से, 60, 000 गांवों में दलहनों और तिलहनों में क्रांति 300 करोड़ रूपए से और मृदा स्वास्थ्य, जल–संरक्षण, और जैव–विविधता परिरक्षण केवल 200 करोड़ रूपए से लाने का वायदा किया गया है।

नवंबर 2009 में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए उल्लेख किया था कि भारत ने 7.94 करोड़ रूपए की चीनी का निर्यात किया जबकि उसने 611.4 करोड़ रूपए की चीनी का आयात किया। दिसम्बर, 2009 में चीनी का निर्यात 12.34 करोड़ था, जबकि चीनी का आयात 216.90 करोड़ था। आंकड़ों से सत्य पर पर्दा डाला जा सकता है। सच्चाई यह है कि 1.10.2009 से 10.03.2010 तक सरकार ने कुल 5,80,498 टन चीनी का निर्यात किया। सरकार ने राष्ट्रीय संकट के शिखर पर रहने के दौरान 5 से भी कम महीनों में 6 लाख टन चीनी का निर्यात क्यों किया। यह कहने से कि हमने अधिक मात्रा में चीनी का आयात किया है, समस्या का समाधान नहीं होता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक ऊंचे होने के कारण सरकार ने अर्थव्यवस्था में स्पष्टतः मुद्रास्फीति का आयात किया।

<u>राजकोषीय घाटा</u>

बजट में राजकोषीय घाटे के आंकड़े सपनों भरी इच्छा है। चालू वर्ष के 6.7 प्रतिशत घाटे के 5.5 प्रतिशत तक घटने की आशा है। निम्नलिखित कारणों से यह आधार त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है :

क. विनिवेश से 40 हजार करोड़ रूपए की प्राप्ति की संभावना नहीं है। सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में शेयरों को केवल 10 प्रतिशत तक कम किया जाना है। प्रबंध नियंत्रण का भी कोई अंतरण नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों में क्रय करने में औसत निवेशक की रूचि अपर्याप्त है। अतः इसी अतिरिक्त घटत के बिना कोई भारी राजस्व नहीं जुटाया जा सकता है। जब केवल 10 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को ऑफलोड किया जाता है, तब केवल संस्थागत निवेशक इन शेयरों को खरीदते हैं।

ख. मैं केवल आशा और प्रार्थना ही कर सकता हूं कि 3–जी स्पैक्ट्रम की नीलामी से 35 हजार करोड़ रूपए प्राप्त किए जा सकते हैं। देश ने 2–जी स्पैक्ट्रम के मनमाने और धोखेभरे नीलामी के कारण पहले ही 60,000 करोड़ रूपए गंवा दिए हैं। 2008 में 2–जी स्पैक्ट्रम 2001 के मूल्यों पर 1651 करोड़ रूपए आवंटित किया जा चुका है, 2008 में जिन्होंने पिछली रात

को ही 2–जी स्पैक्ट्रम 1651 करोड़ रूपए में लिया था, उनकी शैल कम्पनियों के मूल्य USD 2 Billion तथा उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग के भाग के 7,000 करोड़ रूपए ऑफलोड कर दिए। 9 भारतीय लाइसेंसों के लिए एक्सचेकर को 63,000 करोड़ रूपए की हानि हुई। इस समय 3–जी लाइसेंसिंग के थ्रू स्पैक्ट्रम आवंटन पंगु पड़ा है। संचार मंत्रालय पारदर्शी लेन–देन को प्रतिरूद्ध कर रहा है। 3–जी स्पैक्ट्रम के उससे अधिक लेने वाले नहीं होंगे, जिन्होंने पहले ही 2–जी स्पैक्ट्रम प्राप्त कर लिया है। सरकार ने 2–जी स्पैक्ट्रम के धोखेभरे आवंटन के जरिए मार्केट प्रतिबंधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की रूचि का अभाव साफ दिखाई पड़ेगा।

ग. वर्तमान चालू वर्ष के व्यय को कम करके दिखाया हुआ प्रतीत होता है। पृष्ठ 37 पर बजट प्राप्ति दर्शाती है कि 2008–09 में वास्तविक वृद्धि 24.03 प्रतिशत थी। 2009–10 में यह 15.56 प्रतिशत हो सकती है। बजट में माना गया है कि चालू वर्ष में जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की संभावना है, आर्थिक गतिविधियां अधिक होंगी। तब व्यय में वृद्धि केवल 8.53 प्रतिशत होगी। यह ऐसी इच्छा है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। बजट में आशा की गई है कि राजस्व प्राप्त में अगले वर्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप भारत के राजकोषीय घाटे को इस आशा के जरिए नहीं घटा सकते हो कि खर्च कम होगा और कर प्राप्ति बढ़ेगी।

घ. जब आपकी ऑफ बेलेंस शीट मदों को बजट में जोड़ा जाएगा, तब वे आपके राजकोषीय घाटे को प्रतिसंतुलित करेगी। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट में पृष्ठ 32 पर 2 मद निर्दिष्ट है अर्थात net accretions to the National Small Savings Fund (NSSF) and borrowings under the Marketing Stabilization Scheme (MSS) जो राजकोषीय घाटे की गणना में हेतुक नहीं बनाई गई है। इसी प्रकार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अनेक ऑफ बेलेंस शीट मदों को शामिल न करके बजट विभाग के वित्त लेखों के बीच स्पष्ट विसंगति का उल्लेख किया है।

पुनश्चः – **(सोमवार 15–03–2010 को शेष बचे भाषण पर एक नोट जारी किया जाएगा)**

(रामकृपाल सिन्हा)
*सचिव, भाजपा संसदीय दल*